गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 261
दि. 22.01.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

घाटी के साए में छिपा खतरा: जम्मू-कश्मीर में विदेशी आतंकियों का जाल और सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी परीक्षा

(जीएनएस)। जम्मू-कश्मीर एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता के केंद्र में है। घाटी में हालात भले ही सतह पर पहले से अधिक शांत नजर आते हों, लेकिन परदे के पीछे एक जटिल और खतरनाक खेल लगातार चल रहा है। खुफिया एजेंसियों की ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में पाकिस्तान से आए करीब 50 'ए' ग्रेड आतंकी छिपे हुए हैं। ये वे आतंकी हैं जिन्हें अत्यंत प्रशिक्षित, रणनीतिक रूप से सक्षम और लंबे समय तक जंगलों व दुर्गम इलाकों में टिके रहने में माहिर माना जाता है। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कई आतंकियों ने अफगानिस्तान फ्रंट पर आधुनिक युद्ध तकनीकों की ट्रेनिंग ली है, जिससे उनका मुकाबला और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ये आतंकी किसी एक जिले या क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जम्मू के पहाड़ी इलाकों से लेकर कश्मीर घाटी के घने जंगलों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग और शोपियां जैसे इलाके इनके लिए सुरक्षित ठिकाने बनते जा रहे हैं। हाल ही में किश्तवाड़ के छातरू बेल्ट में 12 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर बने एक अस्थायी आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ था। हालांकि मुठभेड़ के दौरान आतंकी वहां से भाग निकलने में सफल रहे, लेकिन पीछे छोड़ा गया राशन, गैस सिलेंडर, सर्दियों के कपड़े और टेंट इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्हें लंबे समय तक टिके रहने के लिए स्थानीय स्तर पर पूरी मदद मिल रही है।

यही वह बिंदु है जहां से सुरक्षा एजेंसियों की असली चुनौती शुरू होती है। आतंकियों से ज्यादा मुश्किल उनका ओवर ग्राउंड वर्कर यानी ओजीडब्लू नेटवर्क है। खुफिया आकलन के मुताबिक, इन करीब 50 आतंकियों के पीछे कम से कम 200 ऐसे लोग सक्रिय हैं, जो सीधे तौर पर हथियार नहीं उठाते, लेकिन आतंकवाद की पूरी रीढ़ बने हुए हैं। ये ओजीडब्लू आतंकियों तक राशन, दवाइयां, गैस, कपड़े और जरूरी सामान पहुंचाने के साथ-साथ सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी भी समय-समय पर साझा करते हैं। कई मामलों में तो यही नेटवर्क आतंकियों को सुरक्षित रास्ते, छिपने की जगह और स्थानीय हालात की पूरी जानकारी देता है।

पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य और अन्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यही नेटवर्क आतंकियों को लगभग अदृश्य बना देता है। आधुनिक तकनीक के बावजूद जब दुश्मन आम नागरिक की शक्ल में मौजूद हो, तो उसे पहचानना बेहद कठिन हो जाता है। ये ओजीडब्लू अक्सर बिना इंटरनेट वाले मोबाइल फोन, कोडेड संदेशों और आम दिखने वाली गतिविधियों के जरिए काम करते हैं। इससे तकनीकी निगरानी यानी टेक्निकल इंटेलिजेंस की प्रभावशीलता काफी हद तक सीमित हो जाती है। स्थिति को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि इस ओजीडब्लू नेटवर्क में कुछ सरकारी महकमों से जुड़े लोगों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर (सेवानिवृत्त) का कहना है कि अतीत में वन, शिक्षा और राजस्व विभागों के कर्मचारियों पर आतंकियों की मदद करने के आरोप लग चुके हैं। ये लोग अपनी सामाजिक पहचान और सरकारी पद का फायदा उठाकर बिना किसी शक के आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं। गांवों और कस्बों में इन्हें सामान्य नागरिक की तरह देखा जाता है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन्हें चिन्हित करना और भी मुश्किल हो जाता है।

हालांकि एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि घाटी में स्थानीय आतंकियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस समय जम्मू-कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकियों की संख्या घटकर लगभग 10 रह गई है। बीते दो वर्षों में मारे गए आतंकियों में करीब 65 प्रतिशत पाकिस्तानी मूल के थे। इसका साफ मतलब है कि स्थानीय युवाओं का आतंक की ओर रुझान पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई सीमा पार से भेजे जा रहे विदेशी आतंकियों से की जा रही है।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब सबसे बड़ी चिंता वे आतंकी हैं, जो सीधे नियंत्रण रेखा के अलावा नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के जरिए भारत में घुसपैठ कर कश्मीर तक पहुंच रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, इस समय एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार करीब आठ आतंकी लॉन्च पैड और कैंप सक्रिय हैं, जहां लगभग 120 आतंकी घुसपैठ के अवसर की तलाश में हैं। सर्दियों में बर्फबारी और खराब मौसम का फायदा उठाकर ये आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस दौरान निगरानी चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

इसी खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि सर्दियों के मौसम में घुसपैठ को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बीएसएफ और सेना अब सीमा पर उन्नत सर्विलांस सिस्टम, थर्मल इमेजिंग, ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। इसके बावजूद अफगानिस्तान में प्रशिक्षित आतंकियों की मौजूदगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक स्थायी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि ये आतंकी लंबे समय तक बिना किसी संपर्क के भी जंगलों में जीवित रहने और हमला करने की क्षमता रखते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद से लड़ते हुए भारी बलिदान भी दिए हैं। राजौरी और कोकेरनाग जैसे इलाकों में हुई मुठभेड़ों ने यह साबित किया है कि सीमा पार से भेजे जा रहे आतंकी बेहद हाईली ट्रेंड और अनुभवी हैं। कोकेरनाग ऑपरेशन में कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष जैसे जांबाज अधिकारियों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इन मुठभेड़ों में सामने आए लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर 'क्वारी' जैसे आतंकियों का सीधा संबंध पाकिस्तान-अफगानिस्तान फ्रंट से था, जो यह दर्शाता है कि आतंक की साजिशें कितनी संगठित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित हैं।

आतंकियों की बदलती रणनीति ने सुरक्षा बलों को भी अपने तौर-तरीके बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब आतंकी सामान्य संचार माध्यमों से दूरी बना रहे हैं, जिससे तकनीकी खुफिया जानकारी जुटाना कठिन हो गया है। ऐसे में सुरक्षा बलों को ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मुखबिरों के नेटवर्क पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। हालांकि, इस तरह की सूचनाओं को सत्यापित करना और उनके आधार पर घने जंगलों व दुर्गम पहाड़ियों में ऑपरेशन चलाना जवानों के लिए जान जोखिम में डालने जैसा होता है।

सनातन धर्म पर बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन को बड़ा झटका, मद्रास हाई कोर्ट ने माना नफरती भाषण

(जीएनएस)। चेन्नई। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म पर दिए गए बयान के मामले में मद्रास हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उदयनिधि स्टालिन का बयान हेट स्पीच यानी नफरती भाषण की श्रेणी में आता है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि द्रविड़ आंदोलन से जुड़ी पार्टियों, विशेष रूप से डीएमके, का पिछले एक शताब्दी से हिंदू धर्म पर सीधा और खुला हमला रहा है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, जिसे उदयनिधि के बयान पर प्रतिक्रिया देने के चलते दर्ज किया गया था।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर देशभर में पहले ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी बहस हो चुकी है। कोर्ट की टिप्पणी ने न केवल इस बहस को फिर से हवा दे दी है, बल्कि नफरती भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर मूल नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि उस पर प्रतिक्रिया देने वालों को कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया जाता है, जो एक चिंताजनक स्थिति है।

मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह रेखांकित किया कि उदयनिधि स्टालिन जिस राजनीतिक परंपरा से आते हैं, उसमें हिंदू धर्म और सनातन परंपरा के खिलाफ वैचारिक विरोध का इतिहास रहा है। अदालत ने कहा कि यह कोई आकस्मिक या एकाकी बयान नहीं था, बल्कि इसे उस लंबे वैचारिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसमें द्रविड़ आंदोलन और उससे निकली पार्टियों ने सनातन धर्म की आलोचना की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने मंत्री के भाषण के 'छिपे हुए अर्थ' पर सवाल उठाया था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि नफरती भाषण देने वाले लोग अक्सर कानूनी सजा से बच जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को यह दर्ज करने में दुख हो रहा है कि समाज को बांटने वाले, आस्था और विश्वास को निशाना बनाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ कानून का सख्ती से पालन नहीं किया जाता। इसके उलट, जो लोग ऐसे भाषणों पर प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हें पूछताछ, एफआईआर और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अदालत ने इसे न्याय व्यवस्था के लिए एक असंतुलन और खतरे की घंटी बताया।

इस मामले में भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि उनके बयान में कोई उकसावा या हिंसा के लिए आह्वान नहीं था। मालवीय ने केवल उदयनिधि स्टालिन के बयान का हवाला देते हुए यह सवाल उठाया था कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री द्वारा सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से करना कितना उचित है। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को सामने रखना और सवाल करना अपराध नहीं है और इस पर भारतीय दंड संहिता की कोई भी धारा लागू नहीं होती।

दरअसल, पूरा विवाद 2 सितंबर 2023 को उस समय शुरू हुआ था, जब उदयनिधि स्टालिन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सनातन धर्म को लेकर बेहद विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, जैसे डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना, बल्कि इन्हें खत्म करना होता है। इसी क्रम में उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को भी खत्म करना होगा। इस बयान के सामने आते ही देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसे हिंदू धर्म और आस्था पर सीधा हमला बताया, जबकि डीएमके समर्थकों ने इसे सामाजिक सुधार और जातिवाद के खिलाफ बयान बताने की कोशिश की।

"सुखना झील को और कितना सुखाओगे?": अरावली से चंडीगढ़ तक पर्यावरण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की अदालत में आज जो शब्द गूंजे, वे केवल कानूनी टिप्पणी नहीं थे, बल्कि देश के पर्यावरण को लेकर एक गंभीर चेतावनी थे। "सुखना झील को और कितना सुखाओगे?" यह सवाल सिर्फ चंडीगढ़ प्रशासन से नहीं था, बल्कि उस पूरे तंत्र से था जिसमें अवैध खनन, अनियंत्रित निर्माण और राजनीतिक–प्रशासनिक मिलीभगत के चलते प्रकृति लगातार हारती जा रही है। अरावली पहाड़ियों में खनन और सुखना झील के आसपास हो रहे अवैध निर्माण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जिस तीखे अंदाज में नाराजगी जताई, उसने साफ कर दिया कि अब अदालत इस मुद्दे को केवल कागजी बहस तक सीमित नहीं रखना चाहती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली भी शामिल थे, ने साफ शब्दों में कहा कि खनन पर रोक के बावजूद अवैध गतिविधियां जारी हैं और अगर इन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो ऐसे हालात बनेंगे, जिन्हें भविष्य में सुधारा ही नहीं जा सकेगा। अदालत का यह कहना अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि यह संकेत देता है कि पर्यावरणीय नुकसान अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां केवल पुनर्वास या मरम्मत से काम नहीं चलेगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि अवैध खनन केवल तत्काल पर्यावरणीय क्षति नहीं करता, बल्कि इसके प्रभाव दशकों तक बने रहते हैं। पहाड़ों की कटाई से जलस्तर गिरता है, नदियों और झीलों में सिल्ट जमा होता है, बाढ़ और सूखे की आशंका बढ़ती है और पूरा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। अरावली जैसी प्राचीन पर्वत श्रृंखला, जो उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक ढाल का काम करती है, अगर कमजोर होती गई तो इसके परिणाम केवल राजस्थान या हरियाणा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे क्षेत्र को झेलने पड़ेंगे। इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले में अब विशेषज्ञों की राय को औपचारिक और संस्थागत रूप से शामिल करेगा। अदालत ने अरावली में खनन और उससे जुड़े सभी पहलुओं की व्यापक जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है। यह समिति पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और खनन विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी और कोर्ट के प्रत्यक्ष निर्देशन व पर्यवेक्षण में काम करेगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एमिकस क्यूरी परमेश्वर को चार सप्ताह के भीतर ऐसे विशेषज्ञों के नाम सुझाने का निर्देश दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब अदालत तथ्यों, वैज्ञानिक आंकड़ों और जमीनी हकीकत के आधार पर आगे का रास्ता तय करना चाहती है।

अरावली के साथ-साथ सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ की सुखना झील का मुद्दा भी केंद्र में आ गया। यह झील केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन की अहम कड़ी है। कोर्ट ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डर माफिया सक्रिय हैं और अवैध निर्माण के चलते सुखना झील को लगभग क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पीठ ने कहा कि पंजाब में राजनीतिक दलों के समर्थन और नौकरशाही की मिलीभगत से जो निर्माण हो रहे हैं, उनके परिणामस्वरूप झील धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है। यह टिप्पणी केवल प्रशासनिक लापरवाही की आलोचना नहीं थी, बल्कि सत्ता, धन और अपराध के उस गठजोड़ पर सीधा प्रहार था, जिसने प्राकृतिक संसाधनों को कमाई का साधन बना दिया है। कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि बार-बार चेतावनियों और आदेशों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आता।

चुनावी रणभूमि के लिए भाजपा ने कसी कमर, नितिन नवीन के नेतृत्व में तय हुई राज्यों की निर्णायक रणनीति

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पद संभालते ही स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा अब किसी भी राज्य में चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। इसी क्रम में बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी संगठन की एक व्यापक और मैराथन समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें देशभर से आए प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। करीब छह घंटे तक चली इस बैठक में चुनावी राज्यों की रणनीति, संगठन की मजबूती, जमीनी फीडबैक और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई।

बैठक के दौरान नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल को लेकर पार्टी के इरादे साफ शब्दों में रखे। उन्होंने दावा किया कि अगला विधानसभा चुनाव भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और राज्य में सरकार बनाएगी। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर नए जोश और आत्मविश्वास के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में नितिन नवीन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी जैसे चुनावी राज्यों में पार्टी को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना होगा और तय की गई रणनीति पर बिना किसी ढिलाई के अमल करना होगा।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रत्येक राज्य की संगठनात्मक स्थिति, बूथ स्तर की तैयारियां, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्यों के नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति, विपक्ष की ताकत और कमजोरियों के साथ-साथ जनता के मूड की रिपोर्ट अध्यक्ष के सामने रखी। इस दौरान यह भी सामने आया कि जिन राज्यों में पार्टी सत्ता में नहीं है, वहां संगठन को और अधिक मजबूत करने तथा जनाधार बढ़ाने की जरूरत है।

नितिन नवीन ने बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया कि संगठन ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और चुनावी सफलता का आधार भी। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक मजबूत और सक्रिय संगठन के बिना चुनाव जीतना संभव नहीं है। इसलिए सभी राज्यों को निर्देश दिए गए कि बूथ कमेटियों को सक्रिय किया जाए, पन्ना प्रमुखों की भूमिका को और प्रभावी बनाया जाए तथा कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास और अनुशासन दोनों बनाए रखना जरूरी है।

बैठक में पूर्व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि भाजपा की चुनावी सफलता का मूल मंत्र जनता से सीधा संवाद और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाना है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष चाहे जितना भी शोर मचाए, भाजपा को अपने काम और संगठन की ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देने से पार्टी को लाभ मिलेगा।

पश्चिम बंगाल को लेकर बैठक में विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जनता में नाराजगी बढ़ रही है और कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दे भाजपा के लिए मजबूत हथियार बन सकते हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य में केंद्रीय नेताओं के दौरे बढ़ाए जाएंगे और जनसभाओं, रैलियों तथा संगठनात्मक कार्यक्रमों के जरिए माहौल बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनावी नैरेटिव तैयार किया जाएगा।

शुद्ध मतदाता सूची से ही मजबूत होगा लोकतंत्र, एसआईआर पर कायम चुनाव आयोग

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लोकतंत्र के लिए अनिवार्य बताते हुए उसका मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, पारदर्शी और मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद एक सही और विश्वसनीय मतदाता सूची होती है और यदि इसमें खामियां हों तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। राजनीतिक दलों की आपत्तियों के बावजूद चुनाव आयोग इस दिशा में अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेगा।

भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित 'लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन' विषय पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के नतीजे यह साबित करते हैं कि इस प्रक्रिया से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि संरक्षण हुआ है। उनके मुताबिक, एसआईआर के दौरान न तो किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया और न ही किसी योग्य मतदाता का नाम हटाया गया, जैसा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा आशंका जताई जा रही थी।

सीईसी ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मतदाता के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से सीधा जुड़ा विषय है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि मृत व्यक्तियों, स्थानांतरित हो चुके लोगों या अयोग्य मतदाताओं के नाम सूची में बने रहते हैं, तो यह न केवल चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, बल्कि वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों को भी कमजोर करता है। इसी कारण विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे कदम समय-समय पर जरूरी हो जाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से आए चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के सामने बोलते हुए ज्ञानेश कुमार ने भारत के चुनावी अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां करोड़ों मतदाता हैं और सामाजिक-भौगोलिक परिस्थितियां बेहद जटिल हैं, वहां मतदाता सूची को अद्यतन रखना एक सतत चुनौती है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने तकनीक, जमीनी सत्यापन और पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए इस चुनौती को अवसर में बदला है।

उन्होंने बिहार के उदाहरण का हवाला देते हुए बताया कि एसआईआर के दौरान घर-घर जाकर सत्यापन किया गया, स्थानीय प्रशासन और बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया और हर स्तर पर शिकायत निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को भी शामिल किया गया और उन्हें सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया गया। सीईसी ने कहा कि इसके बावजूद यह कहना कि एसआईआर लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करता है, तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है।

ज्ञानेश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में काम नहीं करता और उसका एकमात्र उद्देश्य संविधान के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में शुद्धता लाने के प्रयासों को किसी राजनीतिक चश्मे से देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सभी हितधारकों को इस प्रक्रिया में सहयोग करना होगा, न कि संदेह और अविश्वास फैलाना होगा।

संपादकीय

मददवीर अग्निवीर

सेना में अग्निवीर योजना के क्रियान्वयन के वक्त इनकी अल्पकालिक सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद उनके भविष्य को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं। लेकिन अब धीरे-धीरे कई आशंकाएं निर्मूल साबित हो रही हैं। प्रशिक्षित अग्निवीरों के लिये नये-नये अवसर बन रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में गठित होने जा रही डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। यह सुखद ही है कि अग्निपथ योजना के पहले बैच के सेवा काल की समाप्ति से पहले हरियाणा सरकार ने उनके समायोजन की पहल की है, जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। जिससे इस कुशल-प्रशिक्षित युवा शक्ति की ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल की पहल हो सके। दरअसल, हरियाणा में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में अग्निवीरों को वरीयता देने की बात कही गई है। निश्चय ही इस कदम से जहां अग्निवीरों की नई पीढ़ी सामने आएगी, वहीं राज्य को इनके कुशल प्रशिक्षण का लाभ मिल सकेगा। यह भी हकीकत है कि बदलते वक्त के साथ आपदाओं की पुनरावृत्ति व घातकता बढ़ रही है, उससे जूझने के लिये भी अनुभवी व प्रशिक्षित बल की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। जो एक स्थायी, पेशेवर और पूर्णकालिक बल के जरिये ही संभव हो सकता है। दरअसल, हरियाणा में सरकार ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में गठित होने वाली एसडीआरएफ बटालियन में अधिकतम संख्या अग्निवीरों की ही होगी। विश्वास किया जा रहा है कि अग्निवीरों वाली एसडीआरएफ प्राकृतिक आपदाओं मसलन बाढ़,भूकंप, औद्योगिक दुर्घटनाओं, अग्निकांडों व रासायनिक आपदाओं की चुनौती का सफलता से मुकाबला कर सकेगी। माना जा रहा है कि अग्निवीरों को मिला कठोर प्रशिक्षण आपातकालीन स्थितियों से मुकाबले में मददगार साबित होगा। दरअसल, ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में तीव्र गति से कार्रवाई करते नागरिकों के जीवन की रक्षा करने की प्राथमिकता होती है। जो प्रशिक्षित और अनुभवी टीम के द्वारा ही संभव हो सकता है। कहा जा रहा है कि राज्य की सभी डिविजनों में क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात की जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में नोएडा में धुंध के चलते हुई एक सड़क दुर्घटना में एक युवा इंजीनियर की मौत हुई। बेटे को मौत के मुंह में समाते देख असहाय पिता ने पुलिस से मदद मांगी। लेकिन मदद के लिये पहुंची टीम के पास इस चुनौती का मुकाबला करने के लिये जरूरी उपकरण व अनुभव नहीं था। ऐसे में युवा इंजीनियर ने पिता के सामने ही डूबकर दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद आपदा राहत बल को प्रशिक्षित करने और जीवन रक्षा के तमाम उपकरण उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में हरियाणा में एसडीआरएफ बटालियन के गठन और उसमें प्रशिक्षित व अनुभवी अग्निवीरों की तैनाती की घोषणा के बाद उम्मीद जगी है कि हरियाणा की सुरक्षा कुशल हाथों में रहेगी। तब प्राकृतिक, औद्योगिक व आगजनी आदि की घटनाओं में जन-क्षति को कम करने में मदद मिल सकेगी। हालांकि, अब तक हरियाणा में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आईआरबी की बटालियन पहले ही नोडल डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसी के रूप में सक्रिय रही है। इसके अंतर्गत सैकड़ों कर्मचारियों को आपदाओं से निबटने के लिये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लेकिन आपदाओं व दुर्घटनाओं की घातकता के मद्देनजर स्पेशल व स्थायी बल की आवश्यकता लगातार महसूस की जाती रही है। विश्वास किया जाना चाहिए कि अनुभवी नेतृत्व में प्रशिक्षित टीम व आधुनिक जीवन रक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने से एसडीआरएफ तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेगी। निश्चित रूप से अग्निवीरों की सेना में कुशल ट्रेनिंग, अनुशासन के साथ चुनौतियों का मुकाबला करने का प्रशिक्षण व फील्ड में हासिल अनुभव स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को प्रभावी बनाएगा। जिसके आधार पर ही सरकार ने उन्हें एसडीआरएफ बटालियन में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर इससे राज्य में आपदा में तुरंत प्रतिक्रिया क्षमता को संबल मिलेगा। साथ ही अग्निवीरों को अपनी क्षमता प्रदर्शन का नया मंच मिलने से, युवा सेना की अग्निवीर योजना को कैरियर के विकल्प के रूप में चुन सकेंगे।

बर्फबारी-बारिश न होने से फसलों व पेयजल का संकट

> "कश्मीर का 'चिल्लई कलां' इस बार वीरान है। दिसंबर और जनवरी के मध्य तक कश्मीर घाटी में बर्फबारी में 75 से 80 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है।

पिछले दो माह से अधिक समय से कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली और अन्य मैदानी इलाकों में एक बार भी बारिश नहीं हुई है। सूखा और ठंडी हवा ने जनजीवन, कृषि और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसका असर भविष्य में और भी अधिक देखने को मिल सकता है। चिंताजनक बात यह है कि गर्मी के दिन आ रहे हैं और तापमान बढ़ने के साथ-साथ, भारत सहित कई देशों की जीवन रेखा माने जाने वाले हिमालय के पहाड़ बर्फ़ के बिना भूरे नजर आ रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में इस साल 'स्नो ड्राउट' की स्थिति बन गई है। 2025-26 की सर्दियों में इन क्षेत्रों में बर्फबारी सामान्य से 45 से 75 प्रतिशत तक कम रही, खासकर नवंबर-दिसंबर के दौरान। उत्तराखंड में दिसंबर, 2025 में 100 प्रतिशत वर्षा की कमी दर्ज की गई और जनवरी, 2026 तक ऊंचे इलाकों में बर्फ नहीं जमी। बढ़ते तापमान, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है। पिछले पांच वर्षों में बर्फबारी में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है।

कश्मीर का 'चिल्लई कलां' इस बार वीरान है। दिसंबर और जनवरी के मध्य तक कश्मीर घाटी में बर्फबारी में 75 से 80 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों में केवल सूखी घास और नग्न पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यह स्थिति केवल पर्यटन को आर्थिक चोट नहीं पहुंचा रही, बल्कि ग्लेशियरों के पुनर्भरण की प्रक्रिया को भी बाधित कर रही है। यदि बर्फबारी का यह अकाल जारी रहा, तो गर्मियों में झेलम और सिंधु जैसी नदियों का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर तक गिर सकता है, जिससे न केवल पीने के पानी का संकट पैदा होगा बल्कि जलविद्युत परियोजनाओं पर भी ताला लग सकता है।

उत्तराखंड में राज्य के अधिकांश जिलों में सूखे की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य से 97 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई। बारिश न

होना रबी की फसलों खासकर गेहूं के लिए बुरा है। असल में सर्दियों की बारिश केवल पानी की जरूरत पूरी नहीं करती, बल्कि खेतों के लिए खाद का काम करती है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे पोषक तत्व कुदरती रूप से मिलते हैं।

उधर अक्तूबर-नवंबर के गर्म रहने से आलू का अंकुरण कम हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने की मिठास नवंबर की गर्मी ने सोख ली। गन्ने में सुक्रोज बनने के लिए ठंड आवश्यक है लेकिन अभी तक गन्ने में पानी की मात्रा अधिक है। इसलिए गुड़ बन ही नहीं पा रहा था। एक महीने देरी से गुड़ बनना शुरू हुआ है। रबी की फसल बिगड़ने का असर सारे देश की अर्थव्यवस्था और भोजन व्यवस्था पर पड़ना तय है। ऊंचे पहाड़ों पर खेतों में बर्फ का आवरण आमतौर पर एक इन्सुलेशन कंबल के रूप में कार्य करता है। बर्फ की परत से उनकी फसलों की रक्षा होती है, कंद-मूल जैसे उत्पादों की वृद्धि होती है, पाले का प्रकोप नहीं हो पाता। साथ ही बर्फ से मिट्टी का कटाव भी रुकता है। पूरे हिमालय क्षेत्र में कम बर्फबारी और अनियमित बारिश से क्षेत्र में पानी और कृषि वानिकी सहित प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अगर तापमान जल्दी ही बढ़ जाता है तो देर से होने वाली बर्फबारी और भी अधिक त्रासदीदायक होगी। इससे हिमनद झील के फटने से होने वाली बाढ़ अचानक आ सकती है। गर्मी से यदि ग्लेशियर अधिक पिघले तो आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में स्थापित सैकड़ों मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं पर भी संकट आ सकता है। यह भी कड़वा सच है कि पहाड़ों के मिजाज को बिगाड़ने में इन जल विद्युत परियोजनाओं की भूमिका भी है। पहाड़ों पर बर्फ का असर पंजाब की नदियों पर गहराई से होता है।

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भले ही तीव्र ठंड हो, लेकिन बीते चार महीनों से बर्फबारी और बारिश न होने के कारण यहां के पर्यावरण पर अलग किस्म का खतरा मंडरा रहा है। लगातार सूखे से जमीन की नमी समाप्त हो गई है। यदि हालात नहीं सुधरे तो यहां जंगलों में आग का खतरा बढ़ जाएगा। बारिश और बर्फबारी की कमी का असर केवल कृषि तक सीमित नहीं है। यह पूरे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। हिमालयी ग्लेशियरों को पर्याप्त बर्फबारी नहीं मिलने से वे तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नदियों और जल स्रोतों का जलस्तर घट रहा है, जिससे पेयजल और सिंचाई के लिए संकट खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ों पर बरसात और बर्फ न गिरने से जमीन का सूखना वहां के वन्य जीवों के लिए बड़ा खतरा है। हरियाली पर जीने वाले जानवर बस्ती की तरफ आ रहे हैं।

दुखद है कि नीति-नियंता धरती के इस तरह हो रहे नुकसान को जलवायु परिवर्तन के वैश्विक असर या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने की बात कर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं। जबकि अत्यधिक पर्यटन, पक्के निर्माण, पहाड़ों पर तोड़फोड़, हरियाली कवच का कम होना जैसे मानवजनित कारण हैं जिन्होंने हिमालय पहाड़ की गोद में बसे लोगों को समय से पहले संकट में डाल दिया है।

हिमालय के पहाड़ देश के लिए महज मनोरंजन या पर्यटन के लिए नहीं हैं, ये देश की जल-प्रदाय स्रोत हैं। जल किसी कारखाने में बनाया नहीं जा सकता। आज जरूरत है कि हिमालय राज्यों के लिए जलवायु अपरिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि से निपटने को स्थानीय स्तर पर त्वरित और दूरगामी कार्य योजना बनाई जाए, जिसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता और पारंपरिक ज्ञान को भी स्थान मिले।

प्रेरणा

जब समझ जीवन का स्वभाव बन जाए

गुरुकुल का वातावरण बाहर से जितना शांत और व्यवस्थित दिखाई देता था, भीतर उतनी ही गहन साधना चलती रहती थी। वहीं एक शिष्य था जो अपनी तीव्र बुद्धि के लिए जाना जाता था। शास्त्रों की पंक्तियाँ उसके लिए कठिन नहीं थीं, दर्शन के जटिल प्रश्नों पर वह सहजता से चर्चा कर लेता था। उसकी स्मरण शक्ति तेज़ थी और तर्क में वह अक्सर दूसरों को निरुत्तर कर देता था। फिर भी, जब रात के समय वह अकेला बैठता, तो मन के भीतर एक अजीब बेचैनी उठती। ऐसा लगता मानो उसने बहुत कुछ सीख लिया है, पर जीवन में कुछ ठहर नहीं रहा। जितना अधिक वह जानता, उतना ही भीतर का असंतोष गहराता जाता।

उसकी समस्या यह नहीं थी कि उसे जीवन में कोई सुविधा या सम्मान नहीं मिल रहा था। समस्या यह भी नहीं थी कि वह मार्ग से भटक गया था। समस्या कहीं अधिक सूक्ष्म थी। उसका मन स्थिर नहीं रहता था। वह विचारों से भरा रहता, पर वे विचार जीवन को सरल बनाने के बजाय और उलझा देते। अंततः एक दिन उसने अपने गुरु के सामने यह बात रख दी। उसने कहा कि गुरुदेव, ज्ञान तो बढ़ रहा है, समझ भी है, पर भीतर शांति नहीं है। ऐसा क्यों है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है।

गुरु ने उसकी बात को बिना किसी निर्णय के सुना। उन्होंने न तो तुरंत उत्तर दिया और न ही उपदेश का सहारा लिया। वे उसे आश्रम के पीछे ले गए, जहाँ एक साधारण-सा मिट्टी का घड़ा रखा था। घड़ा पानी से भरा हुआ था, लेकिन नीचे एक छोटा-सा छेद था, जिससे पानी धीरे-धीरे टपक रहा था। देखने वाले को लगता कि घड़ा भरा है, पर वास्तविकता यह थी कि वह लगातार खाली हो रहा था। गुरु ने शिष्य से पूछा कि क्या यह घड़ा भरा हुआ है। शिष्य ने उत्तर दिया कि अभी तो है, पर कुछ समय बाद नहीं रहेगा। गुरु ने शांत स्वर में कहा कि यही तुम्हारी स्थिति है। तुम ज्ञान से भरे हुए दिखते हो, पर क्योंकि तुम्हारे जीवन में अनुशासन, अभ्यास और संकल्प की स्थिरता नहीं है, इसलिए यह ज्ञान टिक नहीं पाता। तुम विचारों को ग्रहण तो करते हो, लेकिन उन्हें अपने व्यवहार में स्थायी स्थान नहीं देते। इसीलिए भीतर का खालीपन बना रहता है। गुरु ने घड़े के छेद को बंद कर दिया। कुछ ही क्षणों में पानी का रिसाव रुक गया और घड़ा स्थिर हो गया। उन्होंने कहा कि ज्ञान तभी जीवन को भरता है, जब उसे बहने से रोका जाए और उसे चरित्र में ठहरने दिया जाए।

शिष्य के भीतर यह बात धीरे-धीरे उतरने लगी। उसे समझ आने लगा कि अब तक वह ज्ञान को संग्रह की वस्तु मानता रहा था। जैसे कोई व्यक्ति पुस्तकों या धन को इकट्ठा करता है, वैसे ही वह सिद्धांतों और विचारों को इकट्ठा करता गया। पर जीवन संग्रह से नहीं, साधना से बदलता है। साधना का अर्थ केवल ध्यान या तपस्या नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे-छोटे कर्मों में जागरूकता लाना है। जो जाना है, उसे जीना है।

उसे याद आया कि वह कितनी बार संयम की बात करता था, पर छोटी-सी असुविधा में झुंझला जाता था। वह करुणा के सिद्धांत समझता था, पर जब कोई उसकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो मन कठोर हो जाता था। उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा कि ज्ञान और जीवन के बीच की यही दूरी उसे भीतर से खोखला कर रही थी। उस दिन उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है।

इसके बाद उसके जीवन में एक धीमा लेकिन गहरा परिवर्तन शुरू हुआ। उसने यह निश्चय किया कि वह अब ज्ञान को दिखाने या साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को सरल और सत्य बनाने के लिए अपनाएगा। उसने छोटे संकल्प लिए। यदि उसने शांति के बारे में पढ़ा है, तो वह कठिन परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले रुककर देखेगा। यदि उसने सत्य के बारे में जाना है, तो वह केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने इरादों में भी ईमानदार रहेगा। उसे अनुभव होने लगा कि जब विचार और कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है।

धीरे-धीरे उसने यह भी समझा कि स्थिरता का अर्थ परिस्थितियों से भागना नहीं है। स्थिरता का अर्थ है भीतर ऐसा संतुलन पैदा करना, जो बदलती परिस्थितियों में भी बना रहे। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, लोग प्रशंसा भी करेंगे और आलोचना भी, लाभ भी होगा और हानि भी। ज्ञान का कार्य इन सबके बीच व्यक्ति को केंद्र में टिकाए रखना है। लेकिन यह तभी संभव है, जब ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर न रहे, बल्कि व्यवहार का स्वभाव बन जाए।

समय के साथ शिष्य के प्रश्न बदल गए। पहले वह पूछता था कि कौन-सा ग्रंथ पढ़ना बाकी है, कौन-सा विचार अभी समझ में नहीं आया। अब वह स्वयं से पूछता था कि जो मैंने जाना है, क्या वह मेरे जीवन में दिखाई दे रहा है। यह प्रश्न उसे हर दिन सजग रखता था। उसे महसूस हुआ कि भीतर का खालीपन धीरे-धीरे भर रहा है, क्योंकि अब वह बाहर से कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि भीतर जो है, उसे सहेज रहा था।

गुरु यह परिवर्तन दूर से देख रहे थे। उन्हें पता था कि अब शिष्य के जीवन में वह छेद बंद हो चुका है, जिससे ज्ञान रिस जाया करता था। अब ज्ञान उसमें ठहरेगा, गहराएगा और समय के साथ उसके पूरे जीवन को आलोकित करेगा। यह अनुभव शिष्य के लिए एक मौन शिक्षा बन गया। उसने समझ लिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को बोझिल नहीं, बल्कि सहज बना दे।

यह कथा हमें भी यही सिखाती है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल जानना नहीं, बल्कि रूपांतरित होना है। जब समझ हमारे व्यवहार का स्वभाव बन जाती है, तब मन में खालीपन नहीं रहता। तब जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है, और व्यक्ति भीतर से पूर्णता का अनुभव करता है। यही वह अवस्था है जहाँ ज्ञान और जीवन के बीच कोई दूरी नहीं रहती, और वहीं से सच्ची शांति का जन्म होता है।

न अस्पताल मंदिर रहे, न डॉक्टर ही भगवान

पिछले दिनों एक बड़े चैनल की साइट पर भारत की संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। इसमें शोध करके बताया गया था कि भारत में चवालीस प्रतिशत ऑपरेशन अनावश्यक होते हैं। इसके अनुसार कैंसर के सैंतालीस प्रतिशत, पचपन प्रतिशत दिल, अड़तालीस प्रतिशत गर्भाशय, अड़तालीस प्रतिशत घुटना प्रत्यारोपण, पैंतालीस प्रतिशत सिजेरियन, कंधे का प्रत्यारोपण और रीढ़ की हड्डी के आपरेशन बिना किसी जरूरत के किए जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि जो मीडिया बहुत मामूली बातों पर इतना हाहाकार मचाता है, नफरत के बीज भी बोता है, किसी एक दुर्घटना पर आंसू बहाता है, वहां इस रिपोर्ट की कोई चर्चा नहीं देखी गई। जबकि यह इस देश की समूची जनसंख्या के हितों से जुड़ी थी। आखिर हारी-बीमारी तो हर मनुष्य के जीवन में आती है।

पहले कहा जाता था कि अगर आपका अपना डाक्टर किसी रोग को ठीक नहीं कर पाता, तो अस्पताल चलो। वहां रोग का सही निदान किया जा सकता है। लेकिन उन अस्पतालों को क्या कहा जाए, जो मरीज की बेबसी का फायदा उठाते हैं। बहुत से डाक्टर यदि अस्पतालों की इस मुनाफाखोरी में शामिल नहीं होते, तो उन्हें हटा दिया जाता है।कुछ साल पहले गाजियाबाद में डाक्टर ने एक मरीज से कह दिया कि उसे कोई गम्भीर बीमारी नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने डाक्टर को हटा दिया। जब से अस्पतालों में मार्केटिंग का प्रवेश हुआ है, तो डाक्टरों को दिए गए टारगेट्स को पूरा करना पड़ता है। इसमें अधिक से अधिक मरीजों को लाना, जिन टेस्ट्स की जरूरत नहीं, उन्हें लिखना, मरीज की मृत्यु के बाद भी इलाज के नाम पर उसे भर्ती किए रहना, आदि बातें शामिल हैं। बीमा कम्पनियां इस बात की शिकायत भी कर चुकी हैं कि जब तक मेडिक्लेम का पूरा पैसा अस्पताल नहीं वसूल लेते, वे मरीज को लटकाए रखते हैं। कुछ सालों में गुड़गांव से दो खबरें आ चुकी हैं। ये किसी मीडिया में न आकर फेसबुक पर देखी गई थीं। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एक लड़की बुखार के कारण अपने पति को अस्पताल ले गई । डाक्टर रात भर उसके टेस्ट्स करवाते रहे और अगले दिन दस लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। इसी तरह गुड़गांव के एक बहुत मशहूर अस्पताल के बारे में एक व्यक्ति ने लिखा कि वह दिल के इलाज के लिए दाखिल हुआ। उसे बताया गया कि उसके दो वॉल्व बदलने पड़ेंगे। पैसे जमा करवा दें। लेकिन तभी उसे बुखार आ गया। बुखार में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। चूंकि कमरे का किराया बहुत ज्यादा था, तो मरीज एक होटल में चला गया। वहां उसका एक मित्र आया। मरीज ने उसे बताया कि पहले वह जहां इलाज करा रहा था, वहां तो बताया था कि उसका एक ही वॉल्व खराब है, जबकि यहां दो वाल्व बदलने पड़ेंगे। मित्र उसे एक दूसरे अस्पताल में ले गया। वहां कहा गया कि उसका एक ही वॉल्व बदलना पड़ेगा। जब मरीज ने आकर इस मशहूर अस्पताल के डाक्टर को बताया तो उसने सिर पर हाथ मारते हुए मालिक जो खुद भी बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, उनके बारे में कहा कि मैंने उससे मना किया था, मगर वह नहीं माना। ऐसा ही एक किस्सा लखनऊ के एक अस्पताल बारे में बताया गया। यहां एक मरीज गैस की समस्या के कारण भर्ती हुआ। उससे कहा गया कि दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आठ लाख रुपए जमा कराए। मरीज वहां से जाने लगा, तो उसके साथ अभद्रता भी की गई। खैर, वहां से वह एक दूसरी जगह पहुंचा और दो सौ रुपये की दवा में ठीक हो गया। यहां तक कि बहुत से डाक्टर वे दवाएं लिखते हैं, जो बहुत महंगी होती हैं। वे या तो उसी अस्पताल में मिलती हैं या किन्हीं खास दुकानों पर। मरीज को इसमें भी लूट का सामना करना पड़ता है।

महाराष्ट्र के अस्पतालों के एक सर्वे में पाया गया था कि बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों का वेतन करोड़ों रुपये होता है। इसका कारण भी यही होता है कि जो डॉक्टर अधिक से अधिक मरीजों को भर्ती करते हैं, बिना जरूरत टेस्ट और ऑपरेशन करवाते हैं, उनका वेतन बढ़ता जाता है। मृत मरीजों को वेंटिलेटर पर दिखाकर, उसके परिजनों से खूब पैसा वसूला जाता है। एक मृत बच्चे को एक माह तक वेंटिलेटर पर रखा गया था। बाद में शिकायत करने पर अस्पताल ने उसके परिजनों को पांच लाख रुपये वापस किए थे। कई बार मृत मरीजों पर ऑपरेशन का नाटक करके पैसे वसूले जाते हैं और कह दिया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई।

बहुत सी इंश्योरेंस कम्पनियां भी भारी घोटाले की दोषी पाई गईं। अपने यहां अड़सठ प्रतिशत लोगों के पास बीमा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कम्पनियां कोई न कोई बहाना करके पैसे देने से इनकार कर देती हैं। कई बार अस्पतालों की मिलीभगत से अंगों को निकालने और लगाने के रैकेट्स भी पकड़े गए हैं।

यही नहीं, मुम्बई के एक बहुत बड़े अस्पताल के बाहर डाक्टरों के लिए रेट लिस्ट लगी हुई है कि जो डॉक्टर जितने अधिक मरीज लाएगा, उसे कितना कमीशन दिया जाएगा। टेस्ट्स और दवाओं पर भी भारी-भरकम कमीशन मिलता है।

जिन दवाओं की कीमत कुछ सौ में होती है, उन्हें हजारों में वसूला जाता है। मशहूर पत्रकार स्वर्गीय आलोक तोमर ने अपने कैंसर इलाज के दौरान, इन बातों का भंडाफोड़ बहुत विस्तार से किया था। इस मामले में विदेशी कम्पनियां भी पीछे नहीं हैं। यदि कोई दवा किसी रोग को खत्म कर सकती है, तो उसे कभी बाजार में नहीं लाया जाता। एक मशहूर दवा कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारी ने लिखा था कि हमने दवाएं नहीं बाजार खोजे। यदि कोई दवा अस्थमा को तीन दिन में ठीक कर सकती थी, तो हमने उसे नष्ट कर दिया। यही बात अन्य रोगों के बारे में भी है। रोग को मिटाना नहीं है, उसे बनाए रखना है, जिससे कि आदमी जीवनभर दवा खाता रहे। कम्पनियां मुनाफा कमाती रहें। एक वैज्ञानिक ने डायबिटीज की दवा बनाने वाली एक मशहूर कम्पनी से कहा कि वह इस रोग को खत्म कर सकते हैं। दवा कम्पनी की मालकिन बोली-तब हम क्या करेंगे।

अभियान

तुलसी से जुड़ा सौभाग्य: सही विधि अपनाएं तो घर में टिकती है लक्ष्मी

सनातन धर्म में तुलसी का स्थान अत्यंत पवित्र और विशिष्ट माना गया है। तुलसी केवल एक औषधीय पौधा या आंगन की शोभा नहीं है, बल्कि वह श्रद्धा, आस्था, ऊर्जा और संस्कार का जीवंत प्रतीक है। शास्त्रों में तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और भगवान श्रीहरि विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहां को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और वास्तु की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि तुलसी का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है, जब उसे सही विधि, सही समय और सही स्थान पर लगाया और संभाला जाए। थोड़ी-सी लापरवाही या अज्ञानता इसके सकारात्मक प्रभाव को कमजोर कर सकती है।

तुलसी के कई प्रकार शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनमें रामा तुलसी और श्यामा तुलसी का विशेष महत्व है। रामा तुलसी हल्के हरे रंग की होती है और इसे सौम्यता, शांति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। वहीं श्यामा तुलसी गहरे रंग की होती है और इसे अधिक ऊर्जावान तथा नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाली माना गया है। दोनों ही तुलसी घर में लगाने के लिए शुभ हैं और दोनों का संबंध माता लक्ष्मी की कृपा से जोड़ा गया है। मान्यता है कि जहां तुलसी हरी-भरी और स्वस्थ रहती है, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी लगाने के लिए समय और तिथि का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर तुलसी लगाना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा तुलसी के माध्यम से घर में शांति और संतुलन लाती है। इसके अलावा मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को रामा और श्यामा तुलसी लगाना भी शुभ फलदायी माना गया है। शुक्ल पक्ष को वृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस पक्ष में तुलसी का रोपण विशेष फल देता है। मान्यता है कि इन शुभ दिनों में लगाई गई तुलसी परिवार के सदस्यों के जीवन में तरक्की, स्थिरता और सकारात्मक बदलाव लेकर आती है।

इसके विपरीत कुछ तिथियां और दिन ऐसे भी माने गए हैं, जब भूलकर भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। एकादशी तिथि को तुलसी भगवान विष्णु की आराध्या मानी जाती है और इस दिन तुलसी को विश्राम देने की परंपरा है। इसलिए इस दिन नया पौधा लगाना या तुलसी को तोड़ना वर्जित माना गया है। इसी प्रकार शनिवार, रविवार और अष्टमी तिथि को तुलसी लगाने को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों तुलसी लगाने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं, जिससे घर में आर्थिक बाधाएं, मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए तुलसी जैसे पवित्र पौधे को लगाते समय केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि नियमों का ज्ञान भी आवश्यक है।

तुलसी को किस दिशा में लगाया जाए, यह वास्तु शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। वास्तु के अनुसार, ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर माना गया है। इस दिशा में रामा या श्यामा तुलसी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। यदि किसी कारणवश उत्तर-पूर्व दिशा में तुलसी लगाना संभव न हो, तो उत्तर या पूर्व दिशा भी स्वीकार्य मानी जाती है। तुलसी को ऐसी जगह लगाना चाहिए, जहां उसे पर्याप्त सूर्य प्रकाश और स्वच्छ हवा मिलती रहे। ऐसा माना जाता है कि सुबह की धूप तुलसी के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है और इससे पौधा स्वस्थ रहता है।

तुलसी के पास प्रतिदिन दीपक जलाने की परंपरा भी केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा भाव और ऊर्जा का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। दीपक का प्रकाश वातावरण की नकारात्मकता को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। मान्यता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती। यही कारण है कि कई घरों में सुबह-शाम तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा आज भी जीवित है।

तुलसी की सेवा करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस स्थान पर तुलसी रखी जाए, वह स्थान हमेशा साफ और पवित्र होना चाहिए। गंदगी, कूड़ा-कचरा या अव्यवस्था वाली जगह पर तुलसी रखने से उसके शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां पवित्रता नहीं होती, वहां देवी का वास स्थायी नहीं रहता। इसलिए तुलसी के आसपास नियमित साफ-सफाई करना और उस स्थान को सम्मान देना आवश्यक है।

एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि घर में कभी भी सूखी या पूरी तरह मुरझाई हुई तुलसी को नहीं रखना चाहिए। हरा-भरा तुलसी का पौधा जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि सूखा पौधा नकारात्मकता और दरिद्रता का संकेत माना जाता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए, तो उसे सम्मानपूर्वक हटा देना चाहिए और उचित विधि से नया पौधा लगाना चाहिए। साथ ही रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को न छूने और न ही उसमें जल डालने की परंपरा है, क्योंकि इन दिनों तुलसी को विश्राम दिया जाता है।

वास्तु शास्त्र यह भी स्पष्ट रूप से कहता है कि तुलसी को कभी भी बाथरूम, टॉयलेट या सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए। ये स्थान नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं और इनके समीप तुलसी रखने से घर में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। तुलसी को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए, जहां उसे सम्मान और शुद्ध वातावरण मिल सके।

ज्योतिष और वास्तु दोनों ही शास्त्रों में तुलसी को नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाली और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली माना गया है। रामा और श्यामा तुलसी को घर में लगाने से वातावरण सात्विक बनता है, मन शांत होता है और घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा और सेवा होती है, वहां देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा बनी रहती है। इससे न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है।

तुलसी हमें यह भी सिखाती है कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि शुद्धता, अनुशासन, श्रद्धा और नियमितता से आती है। जब तुलसी को सही नियमों और सच्चे भाव से घर में स्थापित किया जाता है, तो वह केवल एक पौधा नहीं रहती, बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को संतुलित करने वाली शक्ति बन जाती है। यही कारण है कि तुलसी को लगाने से पहले उसके नियम जानना और उनका पालन करना उतना ही आवश्यक है, जितना स्वयं तुलसी लगाना। सही विधि से रोपी गई और श्रद्धा से सींची गई तुलसी वास्तव में घर को दरिद्रता से दूर रखती है और जीवन में स्थायित्व, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

- वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया एवं वन राज्य मंत्री श्री प्रवीन माळी बैठक में उपस्थित रहे
- भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जेसोर अभयारण्य को भालू संरक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया
- मुख्यमंत्री के संरक्षित वन क्षेत्रों में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर विजिटर्स पॉलिसी गाइडलाइंस बनाने के दिशानिर्देश

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 26 वीं बैठक सम्पन्न

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को गांधीनगर में आयोजित स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 26 वीं बैठक में जानकारी दी गई कि बनासकांठा के जेसोर भालू अभयारण्य को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भालू संरक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया तथा राज्य मंत्री श्री प्रवीन माळी की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत विवरण में यह भी बताया गया कि रतनमहल अभयारण्य में बाघ की मौजूदगी देखी गई है और वहां उसके स्थायी रूप से बसने की पूरी संभावनाएं हैं।

इस संदर्भ में एनटीसीए की सहभागिता से इस क्षेत्र में बाघ संरक्षण एवं देखभाल के लिए सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण स्थानीय लोगों को देने की योजना पर भी इस बैठक में सार्थक चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वन विभाग को राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों/विजिटर्स की बढ़ती संख्या के कारण वन्यजीव जगत को किसी भी प्रकार का नुकसान या व्यवधान न हो, इसकी विशेष सावधानी रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने बैठक में इस उद्देश्य से इको-टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विजिटर्स पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार करने के दिशानिर्देश दिए। इस बैठक में गुजरात में तेंदुओं की बढ़ती संख्या तथा रेस्क्यू किए गए तेंदुओं सहित तेंदुओं के लिए निकट भविष्य में अभयारण्य स्थल सुनिश्चित करने की योजना पर भी चर्चा की गई।

इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया तथा राज्य मंत्री श्री प्रवीन माळी के समक्ष अभयारण्य/नेशनल पार्क में सड़क-रास्ते, जल आपूर्ति, ऑप्टिकल फाइबर, रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली के लिए ट्रांसमिशन लाइन आदि से संबंधित लगभग 18 विभिन्न प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए।

विधायकगण सर्वश्री महेश कसवाला, देवाभाई मालम, मालतीबेन महेश्वरी आदि ने सहभागिता करते हुए वन्यजीव संरक्षण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस बैठक का संचालन वन्य प्राणी जगत के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री डॉ. जयपालसिंह ने किया।

इस बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. विनोद राव, हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स डॉ. ए. पी. सिंह सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

गुजरात में रेलवे अवसंरचना का तीव्र विकास,बहु आयामी परियोजनाओं में ऐतिहासिक प्रगति

(जीएनएस)। गुजरात में रेलवे अवसंरचना के विकास कार्य अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2014 से पूर्व जहां वार्षिक पूंजीगत व्यय लगभग 539 करोड़ था, वहीं वर्तमान में यह बढ़कर 17,155 करोड़ तक पहुंच गया है, जो लगभग 29 गुना वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान में राज्य में चल रही बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) तथा अन्य प्रमुख रेलवे परियोजनाओं सहित कुल निवेश लगभग 1,28,000 करोड़ का है। मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने प्रेस कोन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की,

ट्रैक निर्माण एवं मल्टी-ट्रैकिंग

राज्य में 38 ट्रैक निर्माण/मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जो 2,987 किलोमीटर में फैली हुई हैं और जिनकी कुल लागत 41,686 करोड़ है।

हाल ही में स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं

- पश्चिम रेलवे के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में दो महत्वपूर्ण नई रेल लाइन देशलपर–हाजीपीर–लूना (81.771 किमी) एवं वायोर–लखपत (62.686 किमी) नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्री मण्डल ने स्वीकृति प्रदान की है और भुज-नलिया रेल लाइन का वायोर तक विस्तार एवं नलिया–जखाऊ पोर्ट नई रेल

लाइन लगभग 194 किमी रु.3375 करोड़ की लागत से बनाई जाएंगी। सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसंरचना को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगी।

- नलिया–जखाऊ पोर्ट (24.88 किमी) नई ब्रॉडगेज रेल लाइन, यह रेल लाइन भुज–नलिया खंड के नलिया स्टेशन से प्रारंभ होकर जखाऊ बंदरगाह तक जाएगी।

आरओबी/आरयूबी (लेवल क्रॉसिंग उन्मूलन)

लेवल क्रॉसिंग हटाने हेतु 378 रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सड़क यातायात एवं आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध सुविधा मिलेगी। इन कार्यों पर लगभग 10,000 करोड़ की लागत आएगी।

अमृत भारत स्टेशन योजना

राज्य में 87 अमृत स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 18 स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है।

कवच (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली)

- कुल 1,758 किलोमीटर में कवच प्रणाली का कार्य प्रगति पर।
- दिल्ली–अहमदाबाद खंड पर भौतिक कार्य पूर्ण।
- अहमदाबाद–पालनपुर एवं अहमदाबाद–सामाखियाली खंडों में कवच इंस्टालेशन हेतु निविदाएं जारी, अगले दो वर्षों में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।
- पालनपुर–सामाखियाली–गांधीधाम (लगभग 300 किमी) खंड के लिए भी निविदा जारी।
- अहमदाबाद–गेरतपुर (13.42 किमी) खंड कवच से सुसज्जित हो चुका है।

कवच प्रणाली के प्रमुख घटक—ट्रैकसाइड कार्ड रीडर, कम्युनिकेशन टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्टेशन कवच एवं इंजन कवच—SIL-4 स्तर की अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित हैं, जिन्हें भारतीय इंजीनियरों द्वारा विकसित किया गया है।

अन्य प्रमुख परियोजनाएं

तारंगा हिल–आबू रोड, दाहोद–इंदौर, छोटा उदयपुर–धार, भीमनाथ–धोलेरा लॉजिस्टिक हब, नलिया–जखाऊ पोर्ट, मोडासा–शामलाजी, मियागाम–सोमलाया गेज परिवर्तन, अड्राज मोटी–विजापुर, खिजड़िया–अमरेली, समनी–जंबूसर, समालया–तिंबा–नडियाद–पेटलाद, पेटलाद–भद्रण, मियागाम–मालसर सहित कुल लगभग 22 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास

अहमदाबाद स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत दक्षिण फुट ओवर ब्रिज के 42 मीटर स्पान का लॉन्चिंग कार्य 18 घंटों में 16 चालू लाइनों के ऊपर सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। 140 मीट्रिक टन एआरटी क्रेन की सहायता से प्रत्येक 42 मीटर, लगभग 25 टन वजनी स्टील गर्डर का सुरक्षित लॉन्चिंग कर उत्कृष्ट इंजीनियरिंग एवं अंतर-विभागीय समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

स्टेशन पर 17 एकड़ का रूफ प्लाजा, प्लेटफॉर्म 8 से 11 तक कार्य पूर्ण, 16 मंजिला साउथ प्लाजा भवन का निर्माण प्रगति पर, एलिवेटेड रोड का लगभग 65% कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रतिदिन का यात्री फुटफॉल लगभग 1.03 लाख है।

पश्चिम रेलवे द्वारा गुजरात में चल रहे ये समस्त कार्य आधुनिक, सुरक्षित एवं विश्वस्तरीय रेल अवसंरचना के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनसे राज्य के आर्थिक विकास, यात्री सुविधा एवं लॉजिस्टिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भविष्य की योजनाएं

- अहमदाबाद से चलने वाली ट्रेनों की संख्या वर्तमान से तीन गुना करने का लक्ष्य।
- साबरमती में वंदे भारत ट्रेनों के लिए दो चरणों में डिपो स्वीकृत।
- वटवा में 10 पिट लाइन एवं 20 स्टेबलिंग लाइन वाला मेगा कोचिंग डिपो, जिससे लगभग 150 ट्रेनों का संचालन संभव होगा।
- अहमदाबाद–पालनपुर, अहमदाबाद–सूरत, अहमदाबाद–सामाखियाली, पालनपुर–सामाखियाली सहित कई खंडों पर फोर-लेनिंग हेतु सर्वे।
- नया स्टेशन गोपालपुर विकसित किया जाएगा, जिससे गांधीनगर से भुज की ओर ट्रेनों का संचालन बिना रिवर्सल संभव होगा और यात्रा समय में लगभग एक घंटे की बचत होगी।

23 से 25 जनवरी तक कलोल-कड़ी रेलखंड के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 15 और 17 बंद रहेगा

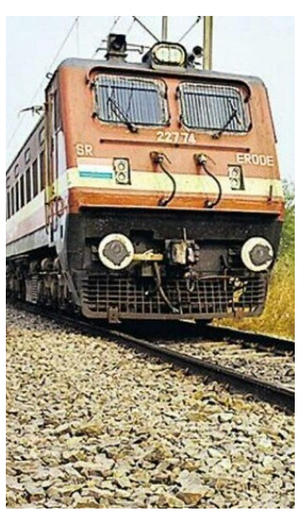

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के कलोल-कड़ी खंड के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 15 और रेलवे क्रॉसिंग नं. 17 ओवरहॉलिंग एवं मशीन टैम्पिंग कार्य हेतु दिनांक 23.01.2026 को प्रातः 08:00 बजे से दिनांक 25.01.2026 को सायं 18:00 बजे तक यातायात हेतु बंद रहेगा। सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान रेल ओवर ब्रिज एवं थोळ आरयूबी (कडी सिटी) का उपयोग कर सकते है।

प्रतापनगर–जोबट एवं आणंद - गोधरा रेलखंड पर ट्रेनों की गति में वृद्धि से यात्रा समय में बचत

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा, समयपालनता में सुधार तथा परिचालन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के अंतर्गत आने वाले प्रतापनगर – जोबट रेलखंड पर 7 ट्रेनों एवं आणंद - गोधरा रेलखंड पर 2 मेमू ट्रेनों की अनुमेय गति में वृद्धि की गई है। इससे संबंधित ट्रेनों के यात्रा समय में कमी आएगी और यात्रियों को समय में बचत के साथ अधिक सुविधाजनक एवं समयबद्ध रेल सेवा का सीधा लाभ प्राप्त होगा।

वडोदरा मंडल के प्रतापनगर–जोबट रेलखंड पर ट्रेनों की गति में वृद्धि के फलस्वरूप ट्रेन संख्या 59122 छोटा उदयपुर - प्रतापनगर पैसेंजर के यात्रा समय में 20 मिनट तक की बचत हुई है, जबकि ट्रेन संख्या 59123 प्रतापनगर - जोबट पैसेंजर के यात्रा समय में 10 मिनट की बचत संभव हुई है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 59124 जोबट - प्रतापनगर पैसेंजर, ट्रेन संख्या 59118 अलीराजपुर - प्रतापनगर पैसेंजर, ट्रेन संख्या 59125 प्रतापनगर – छोटा उदयपुर पैसेंजर, ट्रेन संख्या 59117 प्रतापनगर - छोटा उदयपुर पैसेंजर एवं ट्रेन संख्या 59121 प्रतापनगर - अलीराजपुर पैसेंजर के यात्रा समय में 5 मिनट की बचत हुई है।

इसी प्रकार आणंद गोधरा सेक्शन में रेलखंड पर ट्रेनों की गति में वृद्धि के फलस्वरूप ट्रेन संख्या 69145 आणंद - गोधरा मेमू के यात्रा समय में 10 मिनट एवं ट्रेन संख्या 69146 गोधरा - आणंद मेमू के यात्रा समय में 5 मिनट की बचत संभव हुई है।

पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल यात्रिओं के सेवा में हमेशा प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री फिलिप ग्रीन की गांधीनगर में शिष्टाचार भेंट बैठक

- मुख्यमंत्री ने ओलंपिक खेलों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स फैसिलिटी के सस्टेनेबल उपयोग के ऑस्ट्रेलिया के अनुभव एवं ज्ञान का लाभ लेने के लिए गुजरात की तत्परता व्यक्त की
- राज्य में ओलंपिक खेलों की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को ऑस्ट्रेलिया आने का उच्चायुक्त का निमंत्रण
- गिफ्ट सिटी में कार्यरत डीकिन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स रिसर्च और स्पोर्ट्स बिजनेस जैसे पाठ्यक्रमों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से अलग एक इकोसिस्टम विकसित करेगी
- रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में गुजरात की तीव्र प्रगति से ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त प्रभावित
- रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञता का सहयोग देने की उत्सुकता व्यक्त की

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ओलंपिक खेलों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, आवास और अन्य स्पोर्ट्स सुविधाओं के दीर्घकालीन सस्टेनेबल उपयोग के ऑस्ट्रेलिया के अनुभव एवं ज्ञान का लाभ लेने के लिए गुजरात की तत्परता व्यक्त की। मुख्यमंत्री के साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री फिलिप ग्रीन ओएएम ने गांधीनगर में की गई शिष्टाचार भेंट बैठक के दौरान यह तत्परता दर्शाई।

इस बैठक में आगामी 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाले ओलंपिक खेलों के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर, आवास और अन्य सुविधाओं की तैयारी के लिए की जा रही कवायद को लेकर विस्तृत विचार - विमर्श हुआ।

उन्होंने ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर का खेल समाप्त होने के बाद आम लोगों के आवास, छात्रों के हॉस्टल तथा मैदानों के अन्य आयोजनों के लिए उपयोग करने की योजना का विवरण दिया।

ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने ब्रिस्बेन में की जा रही इन तैयारियों के निरीक्षण के लिए गुजरात के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रण दिया। उन्होंने भूमिका दी कि गुजरात में विशेष रूप से स्विमिंग, पैरा एथलीट्स और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया के सहभागी होने की इच्छा व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका उच्च प्रशिक्षण लाभ गुजरात के खिलाड़ियों को भी मिले और 2036 ओलंपिक में उज्ज्वल प्रदर्शन हो सके; इसके लिए उन्होंने संयुक्त प्रयासों से आगे बढ़ने की अपेक्षा व्यक्त की। मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने गिफ्ट सिटी में कार्यरत डीकिन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स बिजनेस और स्पोर्ट्स रिसर्च के अध्ययन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू कर एक संपूर्ण विशिष्ठ इकोसिस्टम विकसित करने की जानकारी भी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को मार्च 2026 में होने वाले डीकिन यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहने का निमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा वाइब्रेंट समिट में ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी से राज्य के जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, एपैरल एंड क्लोथिंग, लाइफ साइंसेज, फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों को हुए लाभ का उल्लेख किया।

ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त गुजरात द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में ली गई अग्रणी भूमिका से प्रभावित हुए। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का सहयोग गुजरात को देने की तत्परता व्यक्त की।

इतना ही नहीं, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी में सोलर रूफ टॉप के लिए 2000 लोगों की क्षमता के साथ ट्रेनिंग फैसीलिटी विकसित की जा रही हैं तथा इसमें विशेष रूप से महिलाओं की बढ़ती रुचि की भी उन्होंने प्रशंसा की।

इस शिष्टाचार भेंट बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव श्री संजीव कुमार, सचिव श्री अजय कुमार, इंडेक्ष्ट-सी के प्रबंध निदेशक श्री केयूर संपत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाएगी तीन जोड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विशेष किराये पर 03 जोड़ी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

1) ट्रेन संख्या 09009/09010 बांद्रा टर्मिनस–भुज सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09009 बांद्रा टर्मिनस–भुज स्पेशल प्रत्येक रविवार को बांद्रा टर्मिनस से 19:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 09:50 बजे भुज पहुँचेगी। यह ट्रेन 25 जनवरी से 22 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09010 भुज–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक सोमवार को भुज से 14:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 26 जनवरी से 23 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, ध्रांगध्रा, सामाख्याली, भचाऊ तथा गांधीधाम स्टेशनों पर रुकेगी।

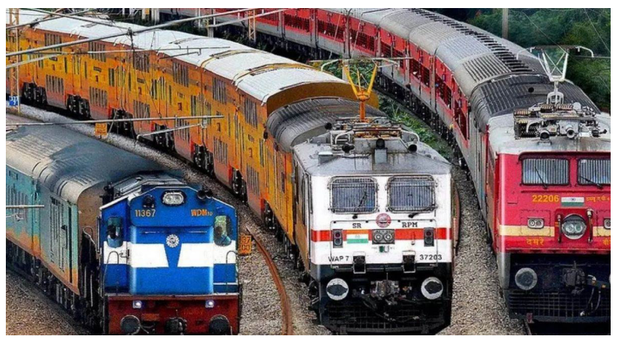

इस ट्रेन में एसी–2 टियर, एसी–3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2) ट्रेन संख्या 09011/09012 बांद्रा टर्मिनस–भुज सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09011 बांद्रा टर्मिनस–भुज स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से 23:55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 14:30 बजे भुज पहुँचेगी। यह ट्रेन 27 जनवरी से 24 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09012 भुज–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक बुधवार को भुज से 17:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 28 जनवरी से 25 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, ध्रांगध्रा, सामाख्याली, भचाऊ तथा गांधीधाम स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी–2 टियर, एसी–3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3) ट्रेन संख्या 09017/09018 बांद्रा टर्मिनस–वेरावल साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09017 बांद्रा टर्मिनस–वेरावल स्पेशल प्रत्येक रविवार को बांद्रा टर्मिनस से 14:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:05 बजे वेरावल पहुँचेगी। यह ट्रेन 25 जनवरी से 22 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09018 वेरावल–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक सोमवार को वेरावल से 11:05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:55 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 26 जनवरी से 23 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, गोंडल, जेतलसर, जूनागढ़ तथा केशोद स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी–2 टियर, एसी–3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09009, 09010, 09011, 09012, 09017 एवं 09018 की बुकिंग 22 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

ऑपरेशन रेल सुरक्षा

उत्राण स्टेशन पर मालगाड़ी से चोरी करने वालों के खिलाफ रेल सुरक्षा बल की सख्त कार्रवाई

(जीएनएस)। विगत दिनों कुछ शरारती तत्वों द्वारा वडोदरा मंडल के उत्राण स्टेशन के यार्ड में खड़ी हुई मालगाड़ी के डिब्बे का सील तोड़कर उसमें लदी हुई चावल की बोरी ले जाने का मामला प्रकाश में आया था । वडोदरा मंडल के रेल सुरक्षा बल के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 14.01.2026 को कुछ शरारती तत्वों द्वारा उत्राण स्टेशन के यार्ड में खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे का सील तोड़ा गया, जिसकी सूचना स्टेशन के पॉइंट्समैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दी गयी। जॉच के दौरान घटना स्थल से करीब 20 फीट की दूरी पर झाडियो में 13 नग चावल की बोरियॉ पड़ी हुई मिली,

जिसका वजन लगभग 625 किलोग्राम था। इस प्रकार चोरी का पुर्ण मुद्दामाल बरामद कर लिया गया। ामले में लिप्त अपराधियो को पकड़ने के प्रयास में रेल सुरक्षा बल द्वारा आसपास की सोसाइटियों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद ली गई। जिसके जरिए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर अपराधियों की पहचान की गई।अंकलेश्वर स्टेशन पर तैनात रेल सुरक्षा बल के निरीक्षक और अपराध शाखा की टीम द्वारा घटना स्थल और उसके आसपास के इलाके की गुप्त निगरानी रखी गई। जिसके बाद दिनांक 18.01.2026 को आरोपियों को पकड़ने की कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी की फुटेज में देखे गये अपराधियो में से एक अपराधी महेश उम्र 23 वर्ष दिखाई दिया, जो सूरत में मजदूरी करता है और गुजरात के सुरेंद्रनगर का निवासी है। पूछताछ करने पर उसने अपने दो साथियो के साथ मिलकर दिनांक 14.01.2026 को उतरायण के दिन रेलवे की मालगाड़ी का सील तोड़कर चावल से भरी बोरियाँ की चोरी कर उसे छुपाना स्वीकार किया। एक अन्य आरोपी सूरत निवासी आकाश उम्र 22 वर्ष को मुखबीर की सूचना की मदद से RPF स्टाफ द्वारा पकड़ा गया, पूंछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर किया। मामले की आगे जॉच जारी है।

वेरावल से बान्द्रा टर्मिनस के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन टिकटों की बुकिंग 22 जनवरी, 2026 (गुरूवार) से शुरू होगी

(जीएनएस)। ट्रेनों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा वेरावल और बान्द्रा टर्मिनस स्टेशन के बीच विशेष किराए पर "स्पेशल ट्रेन" चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इस ट्रेन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

ट्रेन नंबर 09018/09017 वेरावल-बान्द्रा टर्मिनस-वेरावल स्पेशल

ट्रेन नंबर 09017 बान्द्रा टर्मिनस-वेरावल स्पेशल 25 जनवरी, 2025 से 22 फरवरी, 2026 तक प्रत्येक रविवार को बान्द्रा टर्मिनस से दोपहर 14.40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 08.05 बजे वेरावल पहुंचेगी। यह ट्रेन बान्द्रा टर्मिनस से 25 जनवरी, 01 फरवरी, 08 फरवरी, 15 फरवरी और 22 फरवरी, 2026 को चलेगी।

ट्रेन नंबर 09018 वेरावल-बान्द्रा टर्मिनस

स्पेशल 26 जनवरी, 2026 से 23 फरवरी, 2026 तक प्रत्येक सोमवार को वेरावल से सुबह 11.05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन प्रातः 04.55 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन वेरावल से 26 जनवरी, 02 फरवरी, 09 फरवरी, 16 फरवरी और 23 फरवरी, 2026 को चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, गोंडल, राजकोट, सुरेन्द्रनगर जंक्शन, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, सूरत, वापी एवं बोरीवली स्टेशनों पर रूकेगी। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल क्लास कोच होंगे। ट्रेन नंबर 09018 एवं 09017 के लिए टिकटों की बुकिंग 22.01.2026 (गुरूवार) से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्री इस ट्रेन के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

संख्याः W/623/NIT/1 "ई–टेण्डरिंग नोटिस" दिनांक:19.01.26

मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये "खुली निविदा" ई–निविदा के माध्यम से वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है–

क्रम सं.	ई–टेण्डरिंग संख्या और कार्य का नाम	अनुमानित लागत रु.	बयाना राशी रु.
1.	**RTM-2025-26-119R** Dr Ambedkar Nagar (DADN)-Provision of new integrated crew lobby, CTCC Office, counselling room, TRS staff Room with parking & boundary wall at including electric work. **कार्य समापन अवधि:-** 12 Months, **Similar type of work:-** Construction of any Building Work. **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथिः–** 17.01.2026, **निविदा खुलने की तिथिः–** 09.02.2026	₹90,31,074.35	₹1,80,600.00
2.	**RTM-2025-26-120** Chanderia-Development of goods shed with various amenities at. **कार्य समापन अवधि:-** 18 Months, **Similar type of work:- 1.** Any Steel fabrication work Rs. 14,00,70,277.43 **2.** Any Civil Engineering Work Rs. 11,49,39,023.58 The tenderer must have successfully completed or substantially completed any one of the following categories of work(s) during last 07 (seven) years, ending last day of month previous to the one in which tender is invited: (i) Three similar works each costing not less than the amount equal to 30% of advertised value of the tender, or (ii) Two similar works each costing not less than the amount equal to 40% of advertised value of the tender, or (iii) One similar work costing not less than the amount equal to 60% of advertised value of the tender. **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथिः–** 17.01.2026, **निविदा खुलने की तिथिः–**09.02.2026	₹25,50,09,301.01	₹14,25,100.00

अनुमानित मात्रा:- As per tender schedule, **निविदा प्रपत्र का मुल्यः–** Nil • विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है।

5/1/424

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

जब वर्दी उतरी, अदालत बनी दोस्त और इंसाफ ने दौड़ लगाई: 41 दिनों में दरिंदे तक पहुंचा कानून

(जीएनएस)। 7 साल की मासूम से रेप, डर से 7 दिन तक नहीं खोला मुंह फिर पुलिस और जज बने दोस्त; दरिंदे को डेढ़ महीने में मौत की सजा

गुजरात के राजकोट की विशेष पीओसीएसओ कोर्ट और पुलिस ने एक नई मिशाल पेश की है, जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है. पुलिस और न्यायपालिका ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कानून के हाथ अपराधी के कहीं ज्यादा लंबे हैं. 7 साल की बच्ची के साथ हुए रेप मामले में आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस और कोर्ट ने वह काम किया, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है. पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और कोर्ट ने दोस्ती कर ली. कोर्ट और पुलिस ने ऐसा तालमेल मिलाया कि आरोपी को 41 दिनों के अंदर मौत की सजा सुना दी गई.

4 दिसंबर को पीड़िता अपने भाई-बहनों और दूसरे बच्चों के साथ एक खुले मैदान में खेल रही थी. तभी बाइक सवार एक युवक आया और उसे जबरदस्ती एक पेड़ के पास सुनसान जगह पर ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया और 6 इंच की लोहे की रॉड से उस पर जानलेवा हमला किया. जब बच्ची की चीखें सुनकर उसकी चाची मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो चुका था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बच्ची का मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी. अपने साथ हुए हैवानित के बाद बच्ची पूरी तरह से डर गई थी. वह कुछ भी बोलती नहीं थी. पुलिस और वकीलों को देखकर वह कांप जाती थी. घटना के 6 दिन बीत चुके थे और इस दौरान उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया. ऐसे में पुलिस के लिए अपराधी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था. आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर था. मामले की जांच कर रही सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) सिमरन भारद्वाज के पूरा प्लान बदल दिया. उनकी टीम ने आरोपी तक पहुंच बनाने के लिए अपनी वर्दी उतार दी और पीड़िता से दोस्ती कर ली. चॉकलेट से जांच की शुरूआत की गई. धीरे-धीरे जब पीड़िता को यह एहसास हो गया कि यह पुलिस नहीं है, तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी.

पुलिस ने एक पड़ाव पार कर दिया था, लेकिन कठिनाई अभी कम नहीं हुई थी. पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना था. वहीं पुलिस के काम को देखते हुए जज ने भी पुलिस के साथ तालमेल मिलाया और पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए वह प्रिंसिपल बन गईं. एएसपी के अनुसार पीड़िता को स्कूल एडमिशन के लिए इंटरव्यू के नाम पर बयान के तैयार किया गया. उसके लिए नए कपड़े और बैग खरीदे गए.

न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण कपड़ों में स्कूल प्रिंसिपल बनकर पहुंचीं. उन्होंने पहले 6 घंटे पीड़ित के साथ खेला और उसे चॉकलेट खिलाई. जब उसे भूख लगी तो प्रिंसिपल बनी जज ने उसके साथ पानी पूरी खाया. इस तरह से बड़ी ही चालाकी से मजिस्ट्रेट ने दो पन्नों के बयान दर्ज किए. इधर पीड़िता से लगा कि उसके स्कूल एडमिशन का इंटरव्यू पास कर लिया है.

टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) के दौरान भी ऐसा किया गया. आरोपी तक पहुंचने के लिए कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस ने वल्नेरेबल विटनेसेस डिपोजिशन सेंटर (VWDC) का इस्तेमाल किया. जिससे पीड़िता को एक तरफा शीशे के जरिए आरोपी को देखने की अनुमति मिली. एएसपी ने बताया कि पीड़िता की घबराहट कम करने के लिए, मजिस्ट्रेट ने खुद आरोपी समेत हर व्यक्ति को खिलौने पकड़ा दिया था. बच्ची ने आरोपी को खिलौने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लिया.

वकील और पुलिस से पीड़िता न डरे इसके लिए जांच अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने अपनी वर्दी उतार दी और सभी ने सादे कपड़े पहन लिए, बच्ची और उसके परिवार को तैयार करने के लिए एक मॉक कोर्ट आयोजित किया गया. वकील और कोर्ट के कर्मचारी कोर्ट रूप में नहीं थे. जब पुलिस सादे कपड़ों में पीड़िता को कोर्ट रूम लेकर गई, तो वहां अन्य कोई भी मौजूद नहीं था.

इस तरह से कोर्ट और पुलिस की तालमेल के बाद 32 वर्षीय आरोपी रामसिंह दुडवा को FIR दर्ज होने के केवल 41 दिनों के अंदर मौत की सजा सुनाई गई. राजकोट ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर ने बताया कि इस दौरान परिवार के सहयोग के लिए एक अलग टीम लगाई गई थी. इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच 11 दिनों में पूरी कर ली थी.

राजस्थान में SIR को लेकर सियासी घमासान, मतदाता सूची पर आरोप–प्रत्यारोप से गरमाई राजनीति

(जीएनएस)। राजस्थान में गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने हैं और दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कोटा से लेकर बाड़मेर और जयपुर तक इस मुद्दे ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, जहां कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध जता रही है तो बीजेपी इसे नियमों के तहत की जा रही सामान्य प्रक्रिया बता रही है।

कांग्रेस का आरोप है कि SIR की आड़ में बीजेपी अपने राजनीतिक हित साधने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर पर दबाव बना रही है ताकि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाए जा सकें। पार्टी नेताओं का कहना है कि फॉर्म-07 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है और कई जगह BLO एक साथ सैकड़ों हजारों नाम काटने की सिफारिश कर रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रक्रिया में खास तौर पर अल्पसंख्यक और कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को निशाना बनाया जा रहा है।

बाड़मेर में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्थानीय मतदाताओं के नाम यह कहकर हटाए जा रहे हैं कि वे दूसरे जिलों, विशेष रूप से श्रीगंगानगर के निवासी हैं। पार्टी का कहना है कि वर्षों से वहीं रहने वाले लोगों को बाहरी बताकर सूची से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की।

कोटा में भी माहौल तनावपूर्ण रहा, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस का कहना है कि कुछ BLO नियमों की अनदेखी करते हुए बड़ी संख्या में नाम काटने के लिए फॉर्म-07 भर रहे हैं, जबकि उन्हें सीमित संख्या में ही सिफारिश करने का अधिकार है। पार्टी का आरोप है कि यह सब एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले मतदाता सूची को प्रभावित किया जा सके।

जयपुर में मामला तब और तूल पकड़ गया जब कांग्रेस के पूर्व पार्षद अकबरुद्दीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि एक BLO के भाई ने उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म-07 भर दिया और यह दावा किया गया कि वे दिए गए पते पर नहीं रहते, जबकि वे पिछले करीब पचास साल से उसी मकान में रह रहे हैं और वहीं उनका पार्षद कार्यालय भी रहा है। कांग्रेस इसे सत्ता के दबाव में की जा रही कार्रवाई बता रही है।

कांग्रेस ने इस पूरे विवाद को लेकर कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि एक BLO पर नाम काटने का दबाव डाला गया और वह मानसिक तनाव में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं और विधायकों को बुलाकर पेन ड्राइव दी गईं, जिनमें कांग्रेस के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने की सूची थी। टीकाराम जूली ने दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ही करीब 23 हजार मतदाताओं के नाम काटने के लिए फॉर्म-07 भरा गया है।

बीजेपी ने कांग्रेस के इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए जोरदार पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि SIR एक नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखना है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने कई जगह बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाए हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर एक ही मकान में असामान्य रूप से सैकड़ों नाम दर्ज हैं या कोई व्यक्ति गलत पते पर दर्ज है, तो जांच में ऐसे नाम कटेंगे ही।

बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि BLO केवल संदेह के आधार पर आवेदन करता है, अंतिम फैसला चुनाव आयोग जांच और सुनवाई के बाद करता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को किसी नाम को लेकर आपत्ति है तो वह भी आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है। उनके मुताबिक, सही नामों को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

SIR प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने और हटाने के लिए आवेदन की समयसीमा पूरी हो चुकी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजनीतिक दलों की ओर से कुल 18,898 नाम हटाने के आवेदन किए गए, जिनमें से लगभग सभी आवेदन बीजेपी की ओर से हैं, जबकि कांग्रेस ने नाम हटाने के लिए बेहद कम आवेदन किए। आम मतदाताओं की ओर से बड़ी संख्या में नाम जोड़ने और हटाने के आवेदन आए हैं। अब इन सभी आवेदनों पर चुनाव आयोग जांच और सुनवाई के बाद अंतिम फैसला करेगा।

फिलहाल SIR को लेकर राजस्थान की राजनीति में घमासान जारी है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार पर हमला बता रही है, जबकि बीजेपी इसे मतदाता सूची की सफाई की प्रक्रिया कह रही है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग का फैसला इस विवाद की दिशा तय करेगा, लेकिन तब तक यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में बहस और टकराव का केंद्र बना रहने की पूरी संभावना है।

लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए सदनों की सक्रियता अनिवार्य, नियमित बैठकों से ही बनेगा जनविश्वास

(जीएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए राज्य विधानसभाओं की नियमित बैठकों को बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि लोकतंत्र को वास्तव में जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है तो हर राज्य की विधानसभा को वर्ष में कम से कम 30 दिन अवश्य बैठना चाहिए। इससे न केवल सरकार की नीतियों और निर्णयों पर समुचित चर्चा हो सकेगी, बल्कि विपक्ष को भी जनता की आवाज मजबूती से सदन में रखने का अवसर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि विधानसभाएं केवल कानून बनाने की जगह नहीं हैं, बल्कि ये जनता और सरकार के बीच सबसे महत्वपूर्ण सेतु हैं। जनता की अपेक्षा होती है कि उसके चुने हुए प्रतिनिधि उसकी समस्याओं, चिंताओं और आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। यदि सदन कम समय के लिए या बार-बार बाधित होकर चलेगा, तो लोकतंत्र की यह मूल भावना कमजोर होगी। उन्होंने चिंता जताई कि कई राज्यों में विधानसभाओं की बैठकें सीमित दिनों तक ही होती हैं, जिससे न तो गहन बहस संभव हो पाती है और न ही विधायी कार्यों की गुणवत्ता उस स्तर तक पहुंच पाती है, जिसकी अपेक्षा जनता करती है। ओम बिरला ने कहा कि नियमित और सार्थक बैठकों से न केवल कानून बेहतर बनते हैं, बल्कि शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ती है। इससे जनता का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं पर और मजबूत होता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की गरिमा बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाएं चर्चा, सहमति और असहमति के लिए होती हैं, न कि अव्यवस्था और व्यवधान के लिए। नारेबाजी, हंगामा और विरोध के अन्य तरीके लोकतंत्र में अपनी जगह रखते हैं, लेकिन सदन के भीतर इनका अत्यधिक प्रयोग विधायी प्रक्रिया को बाधित करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि विरोध और असहमति के लोकतांत्रिक तरीके सदन के बाहर अपनाए जा सकते हैं, ताकि सदन के भीतर विधायी कार्य निर्बाध रूप से चल सके और जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो सके। ओम बिरला ने यह भी कहा कि आज का दौर तकनीक का है और भारतीय लोकतंत्र भी तेजी से डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। देश की अधिकांश विधानसभाएं अब पेपरलेस प्रणाली अपना चुकी हैं, जिससे कामकाज अधिक सुचारु, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल हुआ है। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से विधायी प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि जनप्रतिनिधि तथ्यों के साथ बेहतर निर्णय ले सकें और जनता को समय पर जानकारी मिल सके। पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल सदन की कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं है।

बिजली सुधार की नई तैयारी, बजट सत्र में बड़ा कदम उठा सकती है सरकार, डिस्कॉम के घाटे पर लगेगी लगाम

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के बिजली क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय असंतुलन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर बड़ा सुधारात्मक कदम उठाने की तैयारी में है। संकेत मिल रहे हैं कि आगामी बजट सत्र के दौरान विद्युत (संशोधन) विधेयक–2025 संसद में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने इस दिशा में सरकार के इरादों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम के लगातार बढ़ते घाटे को कम करने के लिए लागत-अनुरूप शुल्क व्यवस्था को मजबूती से लागू करना बेहद जरूरी है। सरकार का मानना है कि जब तक बिजली आपूर्ति की वास्तविक लागत को टैरिफ में प्रतिबिंबित नहीं किया जाएगा, तब तक वितरण व्यवस्था को आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता।

मनोहर लाल ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय बिजली वितरण कंपनियों के संघ के पहले वार्षिक सम्मेलन ईडीआईसीओएन-2026 के दौरान कही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिजली उत्पादन से लेकर पारेषण और वितरण तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला में अगर किसी कड़ी का सबसे अधिक महत्व है, तो वह डिस्कॉम हैं, क्योंकि उपभोक्ता और बिजली तंत्र के बीच सीधा संपर्क इन्हीं के माध्यम से होता है। उपभोक्ता की शिकायत, उसकी अपेक्षा और उसकी संतुष्टि का स्तर सीधे तौर पर वितरण कंपनियों से जुड़ा होता है। ऐसे में यदि डिस्कॉम कमजोर रहेंगी तो पूरे बिजली क्षेत्र की नींव कमजोर हो जाएगी।

देश की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए बिजली की मांग आने वाले वर्षों में और तेज़ी से बढ़ने वाली है। उद्योग, सेवाएं, डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक वाहन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलों के लिए निरंतर और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ना है, तो पावर सेक्टर को भी उसी गति से सशक्त बनाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि बिजली वितरण कंपनियां घाटे और कर्ज के दलदल से बाहर निकलें और आत्मनिर्भर बनें।

वर्तमान स्थिति यह है कि देश की अधिकांश डिस्कॉम भारी घाटे में चल रही हैं। कई राज्यों में वितरण कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसका सीधा असर न केवल उनकी कार्यक्षमता पर पड़ता है बल्कि पूरे पावर सेक्टर की वित्तीय सेहत भी प्रभावित होती है। उत्पादन कंपनियों को समय पर भुगतान न होने से नई परियोजनाओं में निवेश प्रभावित होता है और अंततः इसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। मनोहर लाल ने कहा कि यह एक दुष्चक्र बन चुका है, जिसे तोड़ने के लिए ठोस और व्यावहारिक सुधार जरूरी हैं।

इसी संदर्भ में प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक–2025 को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्री के अनुसार, इस विधेयक का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिजली आपूर्ति से जुड़ी वास्तविक लागत को टैरिफ में शामिल किया जाए। लागत-अनुरूप शुल्क व्यवस्था से यह होगा कि वितरण कंपनियों को हर यूनिट बिजली पर होने वाले खर्च की भरपाई हो सकेगी और वे लगातार घाटे में जाने से बचेंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे पर किसी एकतरफा फैसले के बजाय संसद में व्यापक चर्चा और सहमति बनाने का प्रयास करेगी। मनोहर लाल ने बताया कि लागत-अनुरूप शुल्क का मतलब यह नहीं है कि उपभोक्ताओं पर अचानक भारी बोझ डाल दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य संतुलन बनाना है, ताकि एक ओर वितरण कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत हों और दूसरी ओर उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा हो सके। इसके लिए पारदर्शी टैरिफ निर्धारण, बेहतर सब्सिडी तंत्र और लक्षित सहायता जैसे उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। मंत्री के मुताबिक, जब व्यवस्था मजबूत होगी, तो उसका सीधा लाभ अंततः उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, क्योंकि बेहतर वित्तीय स्थिति वाली डिस्कॉम सेवा गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगी।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय विद्युत नीति–2026 के मसौदे में भी डिस्कॉम के घाटे और कर्ज को कम करने के लिए लागत-अनुरूप शुल्क को एक अहम आधार के रूप में शामिल किया गया है। इस नीति मसौदे पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं, ताकि इसे अधिक व्यावहारिक और संतुलित बनाया जा सके। मंत्री के अनुसार, इस नीति के तहत जो अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा, उसका उपयोग नियमों के अनुरूप क्रॉस-सब्सिडी देने में किया जा सकेगा, जिससे कमजोर और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को संरक्षण मिलता रहे।

बिजली वितरण व्यवस्था का एक अहम पहलू उपभोक्ता सेवाओं से जुड़ा हुआ है। मनोहर लाल ने कहा कि डिस्कॉम सीधे तौर पर बी2सी सेवाएं देती हैं और बिजली कटौती, बिलिंग, मीटरिंग और कनेक्शन जैसी समस्याओं को लेकर सबसे पहले उपभोक्ता इन्हीं के पास पहुंचते हैं। यदि वितरण कंपनियां आर्थिक दबाव में होंगी, तो सेवा गुणवत्ता पर उसका नकारात्मक असर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सुधार का मकसद केवल वित्तीय आंकड़े सुधारना नहीं, बल्कि उपभोक्ता अनुभव को भी बेहतर बनाना है।

उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक के उपयोग से वितरण तंत्र को अधिक कुशल बनाया जा सकता है। स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल बिलिंग, ऊर्जा ऑडिट और लाइन लॉस कम करने जैसे उपायों से न केवल घाटे में कमी आएगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार इस दिशा में पहले से ही कई योजनाएं चला रही है और प्रस्तावित संशोधन विधेयक इन प्रयासों को और मजबूती देगा।

अस्थिरता के भंवर में फंसा शेयर बाजार, तीसरे दिन भी नहीं लौटी रौनक, निवेशकों की चिंता बढ़ी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में जारी अस्थिरता ने निवेशकों की बेचैनी और बढ़ा दी है। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ और दिनभर चले भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी अंततः लाल निशान में ही टिके रहे। बुधवार को कारोबार की शुरुआत से लेकर अंतिम घंटे तक बाजार में तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच जबरदस्त खींचतान देखने को मिली। हालांकि दोपहर बाद बाजार ने निचले स्तरों से जोरदार वापसी की कोशिश की, लेकिन मुनाफावसूली के दबाव ने उस तेजी को टिकने नहीं दिया और अंत में प्रमुख सूचकांक नुकसान के साथ बंद हुए।

कारोबार समाप्त होने पर बीएसई सेंसेक्स करीब 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी में लगभग 0.30 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई। दिनभर की हलचल यह साफ संकेत देती रही कि बाजार फिलहाल किसी एक दिशा में स्थिर होने को तैयार नहीं है। शुरुआती सत्र में जहां बिकवाली का दबाव हावी रहा, वहीं दोपहर के बाद अचानक आई खरीदारी ने निवेशकों को थोड़ी राहत दी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। बुधवार को जैसे ही बाजार खुला, वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के असर में निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। इसका नतीजा यह रहा कि शुरुआती घंटों में ही सेंसेक्स 1,000 अंकों से ज्यादा टूट गया और निफ्टी भी 300 अंकों से अधिक फिसल गया। इस गिरावट से बाजार में डर का माहौल बन गया और कई निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने के लिए मुनाफावसूली की ओर बढ़ते नजर आए। हालांकि, दोपहर बाद तस्वीर कुछ बदली। निचले स्तरों पर वैल्यू बायिंग सामने आई और चुनिंदा बड़े शेयरों में खरीदारी बढ़ने से बाजार ने जोरदार वापसी की। सेंसेक्स अपने निचले स्तर से करीब 1,280 अंकों से अधिक उछल गया, जबकि निफ्टी ने भी लगभग 380 अंकों की रिकवरी दिखाई। इस तेजी से यह उम्मीद जगी कि शायद बाजार अंत में हरे निशान में बंद हो सकता है, लेकिन अंतिम कारोबारी घंटे में एक बार फिर बिकवाली हावी हो गई और बाजार की दिशा पलट गई। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार की मौजूदा कमजोरी के पीछे एक नहीं, बल्कि कई कारण जिम्मेदार हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से लगातार हो रही बिकवाली ने बाजार की धारणा को कमजोर बनाए रखा है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर व्यापार को लेकर बनी अनिश्चितता, अमेरिका और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े संकेत, डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे कारक भी निवेशकों को सतर्क रहने पर मजबूर कर रहे हैं।

दिसंबर तिमाही के नतीजों ने भी बाजार को कोई ठोस दिशा नहीं दी है। कई कंपनियों के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं, जबकि कुछ ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस मिले-जुले संकेत ने निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है। यही वजह है कि बाजार में लगातार तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कोई भी तेजी लंबे समय तक टिक नहीं पा रही है।

सेक्टर के लिहाज से देखें तो बुधवार को फार्मा, बैंकिंग और एफएमसीजी जैसे दिग्गज सेक्टरों में बिकवाली का दबाव साफ नजर आया। बैंकिंग शेयरों में कमजोरी का असर बाजार पर सबसे ज्यादा पड़ा, क्योंकि इनका वेटेज प्रमुख सूचकांकों में काफी ज्यादा है। फार्मा सेक्टर में भी निवेशकों ने सतर्कता दिखाई और मुनाफावसूली का रुख अपनाया। एफएमसीजी शेयरों में भी दबाव देखने को मिला, जो आमतौर पर बाजार के कमजोर दौर में सुरक्षित माने जाते हैं।

इसके अलावा आईटी, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसई और टेक इंडेक्स भी कमजोरी के साथ बंद हुए। आईटी सेक्टर पर वैश्विक आर्थिक सुस्ती और अमेरिकी बाजारों से जुड़े संकेतों का असर दिखा, जबकि ऑटो सेक्टर में मांग को लेकर चिंताओं ने निवेशकों को दूर रखा। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टरों में भी खरीदारी का उत्साह नजर नहीं आया।

हालांकि बाजार की इस कमजोरी के बीच कुछ सेक्टर ऐसे भी रहे, जहां सीमित खरीदारी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस तथा मेटल सेक्टर के चुनिंदा शेयरों में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई। कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और कुछ मेटल कंपनियों के बेहतर आउटलुक ने इन सेक्टरों को सहारा दिया, लेकिन यह समर्थन इतना मजबूत नहीं था कि पूरे बाजार की दिशा बदल सके।

ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहां भी गिरावट का असर साफ दिखाई दिया। बीएसई मिडकैप इंडेक्स लगभग 1.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.80 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली यह संकेत देती है कि निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं और सुरक्षित रणनीति अपना रहे हैं।

बाजार में आई इस गिरावट का सीधा असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 454.37 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले कारोबारी दिन 455.82 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह महज एक कारोबारी दिन में निवेशकों की संपत्ति से करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये साफ हो गए। लगातार तीसरे दिन नुकसान झेल रहे निवेशकों के लिए यह आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है।

सोना-चांदी में तेजी की आगेकूच जारी: सोना वायदा में 7115 रुपये और चांदी वायदा में 9104 रुपये का ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 427918.3 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 109544.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 318366.24 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 43501 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 9974.46 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 92871.21 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 151575 रुपये के भाव पर खूलकर, 158339 रुपये के दिन के उच्च और 151575 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 150565 रुपये के पिछले बंद के सामने 7115 रुपये या 4.73 फीसदी की मजबूती के साथ 157680 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 9444 रुपये या 7.68 फीसदी की तेजी के संग 132401 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 1300 रुपये या 8.44 फीसदी की तेजी के संग 16706 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 151400 रुपये के भाव पर खूलकर, 158780 रुपये के दिन के उच्च और 151400 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 7442 रुपये या 4.95 फीसदी की तेजी के संग 157926 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 152034 रुपये के भाव पर खूलकर, 159500 रुपये के दिन के उच्च और 152034 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 151113 रुपये के पिछले बंद के सामने 8013 रुपये या 5.3 फीसदी की तेजी के संग 159126 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 322566 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 335521 रुपये और नीचे में 320007 रुपये पर पहुंचकर, 323672 रुपये के पिछले बंद के सामने 9104 रुपये या 2.81 फीसदी की तेजी के संग 332776 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 9510 रुपये या 2.91 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 336111 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 9551 रुपये या 2.92 फीसदी की तेजी

▶▶ क्रूड ऑयल वायदा 52 रुपये बढ़ा: कमोडिटी वायदाओं में 109544.87 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 318366.24 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 92871.21 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 43501 पॉइंट के स्तर पर

के संग 336169 रुपये प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 4741.59 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 16.85 रुपये या 1.31 फीसदी की तेजी के संग 1302.5 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 3.15 रुपये या 1.01 फीसदी बढ़कर 314.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.95 रुपये या 0.62 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 316.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 2.9 रुपये या 1.53 फीसदी की तेजी के संग 192.85 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 11526.18 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5480 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5576 रुपये और नीचे में 5455 रुपये पर पहुंचकर, 52 रुपये या 0.94 फीसदी बढ़कर 5569 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 52 रुपये या 0.94 फीसदी की मजबूती के साथ 5569 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 356 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 445.7 रुपये और नीचे में 355.2 रुपये पर पहुंचकर, 351 रुपये के पिछले बंद के सामने 72.1 रुपये या 20.54 फीसदी की तेजी के संग 423.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 71.7 रुपये या 20.41 फीसदी की तेजी के संग 423 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 971 रुपये के भाव पर खूलकर, 60 पैसे या 0.06 फीसदी चढ़कर 959 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 61047.54 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 31823.68 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3910.23 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 434.73 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 61.53 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 329.30 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 767.37 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 10748.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 11.28 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20015 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 83096 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28173 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 447351 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 51783 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14417 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 38740 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 104274 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17279 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 33303 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 42400 पॉइंट पर खूलकर, 43999 के उच्च और 42400 के नीचले स्तर को छूकर, 1777 पॉइंट बढ़कर 43501 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 29.2 रुपये की बढ़त के साथ 281.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 8.6 रुपये की बढ़त के साथ 8.8 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 5694.5 रुपये की बढ़त के साथ 8356 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 320000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4859.5 रुपये की बढ़त के साथ 21500.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6.98 रुपये की बढ़त के साथ 15.59 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 18 पैसे के सुधार के साथ 1.2 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 12.6 रुपये की गिरावट के साथ 225.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 35.35 रुपये की गिरावट के साथ 16.6 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1311 रुपये की गिरावट के साथ 770 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 320000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4249 रुपये की गिरावट के साथ 8496.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 6.49 रुपये की गिरावट के साथ 4.08 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 51 पैसे की नरमी के साथ 0.2 रुपये हुआ।